माँग-प्रेरित एवं लागत-प्रेरित स्फीति में अन्तर

क्र. सं	अन्तर का आधार	माँग-प्रेरित स्फीति	लागत-प्रेरित स्फीति
1.	**कारण**	इस स्फीति के उत्पन्न होने का मुख्य कारण वस्तुओं और सेवाओं की माँग में वृद्धि है।	इस स्थिति के उत्पन्न होने का कारण लागत में वृद्धि है।
2.	**बाजार की पूर्णता**	माँग-प्रेरित स्फीति तब उत्पन्न होती है जब सार्वजनिक व्यय की पूर्ति हेतु मुद्रा की मात्रा बढ़ायी जाती है।	लागत-प्रेरित स्फीति बाजार की अपूर्णता के कारण पैदा होती है।
3.	**विद्यमानता**	यह स्फीति पूर्ण रोजगार की अवस्था के बाद उत्पन्न होती है।	यह स्फीति बेरोजगारी की स्थिति में पायी जाती है।
4.	**नियन्त्रण**	इस स्फीति को माँग में कमी करके या उत्पादन बढ़ाकर नियन्त्रित किया जा सकता है।	इस स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए मजदूरी पर नियन्त्रण एवं बाजार अपूर्णताओं को दूर करना आवश्यक है।

उपरोक्त अन्तर होते हुए भी माँग-प्रेरित और लागत-प्रेरित स्फीति दोनों इस प्रकार एक-दूसरे से गुँथे हुए हैं कि इनमें भेद करना कठिन हो जाता है।

(III) गतिहीन स्फीति (स्टैगफ्लेशन) (Stagflation)

'Staglfation' शब्द दो शब्दों—Stagnation तथा Inflation से मिलकर बना है जो इस बात का प्रतीक है कि अर्थव्यस्वथा में एक ओर तो कीमतें बढ़ती हैं तथा दूसरी ओर, आर्थिक विकास अवरुद्ध होकर अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता एवं जड़ता की स्थिति आ जाती है। इस स्थिति को ही गतिहीन स्फीति की स्थिति कहते हैं।

इस प्रकार गतिहीन स्फीति में मन्दी के साथ-साथ मुद्रा-स्फीति अर्थात् कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ बेरोजगारी की वृद्धि दिखायी पड़ती है। संक्षेप में, स्टैगफ्लेशन में मुद्रा-स्फीति, महँगाई, बेरोजगारी तथा उत्पादन में जड़ता साथ-साथ चलती हैं।

गतिहीन स्फीति उत्पन्न होने के कारण (Causes for Stagflation)—गतिहीन स्फीति उत्पन्न होने के विभिन्न कारण बताये जाते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं :

(1) **मिश्रित अर्थव्यवस्था** (Mixed Economy)—सैम्युअलसन की मान्यता है कि गतिहीन स्फीति का मुख्य कारण 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' है। आधुनिक युग में सभी देशों में जनता को अधिकाधिक रोजगार देने की नीति अपनाने की प्रवृत्ति पायी जाती है। अधिक रोजगार देने के लिए उदार मौद्रिक नीति अपनायी जाती है। इतना ही नहीं, मूल्यों की सामान्य दर से बढ़ने की प्रवृत्ति को उचित नीति माना जाता है। अत: मूल्य स्थायित्व के लिए सरकार कोई प्रयत्न नहीं करती। यहाँ तक कि फसलें बढ़िया होने पर भी सरकार मूल्यों को नीचे नहीं आने देती। इस प्रकार मूल्य निरन्तर ऊँचे बने रहते हैं। भारत तथा अनेक एशियाई देशों में इसके उदाहरण मिल सकते हैं।

(2) **प्राकृतिक प्रकोप** (Natural Calamities)—प्रो. सैम्युअलसन का यह भी मत है कि प्राकृतिक प्रकोपों, जैसे—सूखा, बाढ़ आदि के कारण भी गतिहीन स्फीति उत्पन्न हो जाती है। एशिया और अमेरिका के देशों में निरन्तर सूखा पड़ने और बाढ़ आने से खाद्यान्नों में कम उत्पादन के कारण उनकी कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार तेल तथा कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई। इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का व्यापक प्रभाव पड़ा किन्तु इससे रोजगार और उत्पादन की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। सैम्युअलसन ने इसे व्यष्टि आर्थिक वस्तु स्फीति (Micro Economic Commodity Inflation) की संज्ञा दी है।

(3) **लम्बे समय तक स्फीतिजनक शक्तियों की विद्यमानता** (Existance of Inflationary Conditions Long Period)—"गतिहीन स्फीति की अवस्था उस समय उत्पन्न होती है, जबकि अर्थव्यवस्था में

Scanned with CamScanner

स्फीतिजनक परिस्थितियाँ एक लम्बी अवधि तक विद्यमान रहती हैं। कीमतों में असाधारण वृद्धि के कारण वास्तविक आय कम हो जाती है। फलतः वस्तुओं और सेवाओं की माँग में कमी आ जाती है। एक सीमा तक बढ़ती हुई कीमतें उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करती हैं लेकिन इसके बाद माँग प्रायः स्थिर हो जाती है अथवा कम होने लगती है तत्पश्चात् उत्पादन में वृद्धि का क्रम रुक जाता है। स्फीति के कारण लागतें बढ़ती हैं, कीमतों में वृद्धि होती है, उत्पादन में अनिश्चितता पैदा हो जाती है और लागत और कीमत का सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पादन में अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।"

(4) **स्फीति के नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय** (Measures to Control Inflation)—स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए जो उपाय अपनाये जाते हैं, उसके बाद मन्दी या अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है। साख को नियन्त्रत करने के लिए मुद्रा की माँग पर जो प्रतिबन्ध लगाये हैं, उससे उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों में कमी हो जाती है। ब्याज की दरों में वृद्धि विनियोग क्रियाओं को हतोत्साहित करती है। आय को नियन्त्रित करने के लिए जो उपाय अपनाये जाते हैं, इससे कुल माँग में कमी हो जाती है। इस प्रकार ये उपाय उत्पादन की मात्रा को पहले की अपेक्षा कम कर देते हैं फलतः स्फीतिक व अस्फीतिक दोनों ही प्रकार के दबावों का सह-अस्तित्व रहता है।

(5) **आयातित स्फीति** (Imported Inflation)—गतिहीन स्फीति का एक कारण यह भी है कि अमेरिका निरन्तर कच्चा और निर्मित माल विदेशों से आयात करता है। फ्रांस, जर्मनी आदि देशों ने भी अपने आयातों को पर्याप्त उदार रखा है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि ने माल खरीदकर जो भुगतान किये हैं तथा विकासशील तथा अन्य देशों को जो ऋण दिये हैं, उनसे इन देशों के बैंकों के कोषों में वृद्धि हुई है जिससे तीव्र गति से साख निर्माण हुआ है और स्फीतिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला है। इन प्रवृत्तियों ने रोजगार तथा उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया।

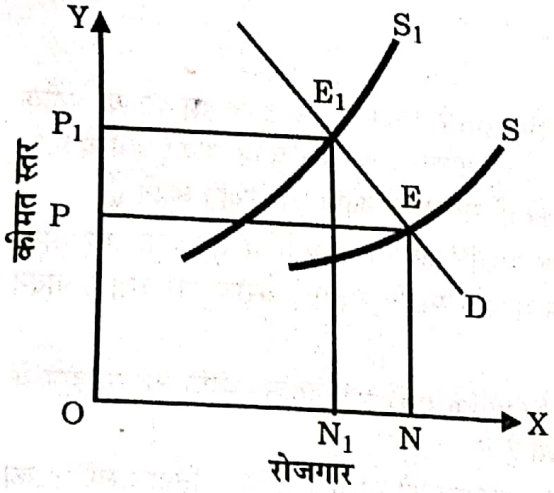

चित्र 5.6

गतिहीन स्फीति की स्थिति को संलग्न चित्र द्वारा दर्शाया गया है। चित्र में :

(i) OX-अक्ष पर रोजगार और OY-अक्ष पर कीमत-स्तर को दर्शाया गया है।

(ii) प्रारम्भिक साम्य स्थिति E है जहाँ पर माँग वक्र (D), पूर्ति वक्र (S), कीमत-स्तर OP और रोजगार स्तर ON है।

(iii) जब उपर्युक्त कारणों में से किसी के कारण समस्त पूर्ति घट जाती है तो पूर्ति वक्र बायीं ओर खिसकर S_1 हो जाता है, नया साम्य E_1 बिन्दु पर स्थापित होता है जहाँ नया पूर्ति वक्र S_1 माँग वक्र (D) को काटता है।

(iv) नये सन्तुलन बिन्दु E_1 पर कीमत-स्तर बढ़कर OP_1 हो जाता है परन्तु रोजगार का स्तर ON से गिरकर ON_1 हो जाता है। यह गतिहीन स्फीति की स्थिति है।

गतिहीन स्फीति के नियन्त्रण के उपाय (Measures to Control Stagflation)—वर्तमान आर्थिक नीतियों के निर्धारकों एवं अर्थशास्त्रियों के सामने इस परस्पर-विरोधी स्थिति का समाधान एक चुनौती है। प्रतिष्ठित मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के पास गतिहीन स्फीति या मुद्रा-स्फीति के साथ मन्दी जैसी समस्या का कोई समाधान नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुभव से पता चलता है कि गतिहीन स्फीति को प्रतिबन्धात्मक अथवा विस्तारशील उपायों से नियन्त्रित किया जायेगा तो वह बढ़ेगा जैसा कि संलग्न चित्र में स्पष्ट किया गया है।

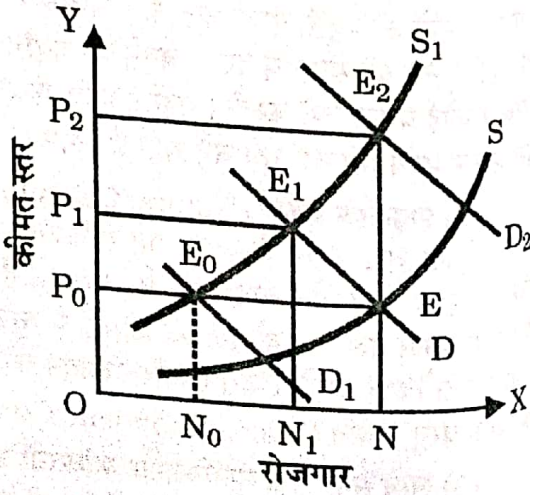

चित्र 5.7

Scanned with CamScanner

(i) मान लीजिए कि प्रतिबन्धात्मक माँग, प्रतिबन्धित मौद्रिक एवं राजकोषीय उपाय अपनाये जाते हैं तो वे समस्त माँग को घटा देंगे और नया माँग वक्र D_1 पूर्ति वक्र S_1 को पुराने कीमत-स्तर OP_0 पर काटेगा।

(ii) इस नीति से रोजगार का स्तर और गिरकर ON_0 पर आ जाता है और इसके साथ ही कीमत-स्तर भी OP_1 से गिरकर OP_0 हो जाती है।

(iii) इस प्रकार इस तरह की नीति से N_1N_0 में बेरोजगारी बढ़ती है और P_1P_0 मात्रा में स्फीति घट जाती है। इस प्रकार यह नीति गतिहीन स्फीति को रोकने में असमर्थ है।

(iv) दूसरी ओर, यदि विस्तारशील माँग, प्रतिबन्धित मौद्रिक एवं राजकोषीय रीतियाँ अपनायी जाती हैं तो वे समस्त माँग को बढ़ा देंगी जिससे नया माँग वक्र D_2 पूर्ति वक्र S_1 को E_2 पर पुराने रोजगार स्तर ON पर काटेगा।

(v) इसका परिणाम यह होता है कि रोजगार स्तर ON_1 से बढ़कर ON पर चला जाता है। इस प्रकार यह नीति भी गतिहीन स्फीति को रोकने में असमर्थ है क्योंकि यह अधिक रोजगार के साथ अधिक स्फीति को उत्पन्न करती है।

गतिहीन स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए उपर्युक्त के अतिरिक्त जो **अन्य सुझाव** दिये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :

(i) **आय नीति** (Income Policy)—गतिहीन स्फीति की समस्या के समाधान के लिए कर पर आधारित आय नीति का भी सुझाव दिया जाता है। इस सुझाव के अनुसार निगमों की आय पर एक अधिभार लगाया जाना चाहिए। जब भी किन्हीं कर्मचारियों की मजदूरी एवं वेतन में वृद्धि करें तो उस पर अधिभार लगाया जाना चाहिए। दूसरी ओर, यदि कोई निगम सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी वृद्धि के मापदण्ड से कम मजदूरी वृद्धि रखे तो उसे कर में कुछ राहत दी जाये। अर्थशास्त्रियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर पर आधारित आय नीति का उद्देश्य सरकार की कर प्राप्तियों में वृद्धि करना नहीं है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को यदि अधिभार एवं कम मजदूरी देने वाले निगमों को दिये जाने वाले भुगतान से जो भी लाभ हो, उसे निगमों के करों को कम करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार इस सुझाव का उद्देश्य यह है कि निगमों के मालिक श्रमिकों की मजदूरी में अधिक वृद्धि न करें। यदि इस दिशा में सरकार को सफलता प्राप्त हो जाती है तो स्फीति पर कुछ सीमा तक नियन्त्रण रखा जा सकता है।

यह सुझाव नया नहीं है, परन्तु इसकी सफलता संदिग्ध है। श्रमिक संघों का इतिहास एवं मजदूरी वृद्धि के उदाहरण इसके प्रमाण हैं।

(ii) **करारोपण सम्बन्धी उपाय** (Taxation Measures)—गतिहीन स्फीति को दूर करने के लिए यह भी सुझाव दिया जाता है कि व्यक्तिगत तथा व्यापार कर घटा दिये जायें क्योंकि वे श्रम लागतें घटाते हैं और श्रम के लिए माँग बढ़ा देते हैं। इस प्रकार बिक्री कर व उत्पादन शुल्क घटा दिये जायें ताकि कीमत-स्तर को बढ़ने से रोका जा सके। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि राज्य तथा स्थानीय बिक्री कर और उत्पादन शुल्क घटाने को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करे।

(iii) **अन्य सुझाव** (Other Suggestions)—(अ) न्यूनतम मजदूरी बिल्कुल न बढ़ायी जाये। (ब) नयी आय नीति चालू करने की जरूरत है। आय नीतियों का एक महत्वपूर्ण आय स्तम्भ यह है कि मजदूरी की वृद्धि को उत्पादकता वृद्धि से सम्बद्ध किया जाय। (स) उत्पादन वृद्धि के लिए आयातित साधनों पर निर्भर न रहकर देश के ही साधनों का पर्ण दोहन किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner